

## Weekly One Liners 11<sup>th</sup> to 17<sup>th</sup> May, 2026

### PM मोदी का UAE दौरा: भारत और UAE ने की 7 बड़े रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) का दौरा किया है, दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच इस हाई लेवल मीटिंग में कई नतीजे सामने आए हैं, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर में सात बड़े एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं।

#### हस्ताक्षरित समझौतों की सूची

1. स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व पार्टनरशिप के साथ मेजर एनर्जी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (ISPRL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच है।

यह पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की लॉन्ग-टर्म एनर्जी रेजिलिएंस को मजबूत करेगी।

इस सहयोग से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व सहयोग, मज़बूत कूड ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित सहयोग और भविष्य में LPG इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी ध्यान देने की उम्मीद है।

क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड एनर्जी पर निर्भर है, इसलिए ग्लोबल सप्लाई में रुकावट के दौरान ये स्ट्रेटेजिक रिज़र्व पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी हैं।

2. दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति समझौता

भारत और UAE ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सप्लाई के लिए डेडिकेटेड एग्रीमेंट पर भी साइन किए।

यह ज़रूरी है क्योंकि LPG देश में घरों और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एक ज़रूरी फ्यूल सोर्स बना हुआ है।

एक स्थिर लंबे समय की सप्लाई व्यवस्था मदद करती है,

- आपूर्ति अनिश्चितता को कम करें
- घरेलू ईंधन सुरक्षा को भी मजबूत करें
- ऊर्जा नियोजन की पूर्वानुमेयता में सुधार
- और भारत की बढ़ती एनर्जी डिमांड को सपोर्ट करें

3. भारत-यूएई रणनीतिक रक्षा साझेदारी

इस दौरे की एक बड़ी खास बात स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है।

इस समझौते से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ेगा।

इस समझौते में शामिल हैं,

- रक्षा विनिर्माण
- सैन्य नवाचार
- सशस्त्र बल प्रशिक्षण
- समुद्री सुरक्षा सहयोग
- साइबर रक्षा सहयोग
- सुरक्षित संचार प्रणालियाँ

यह पूरी तरह से आर्थिक संबंधों से गहरे सुरक्षा तालमेल की ओर बदलाव को दिखाता है।

4. गुजरात का वडिनार बड़े मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तैयार इसके अलावा, गुजरात के वडिनार में प्रस्तावित शिप रिपेयर और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर भी एक बड़ा नतीजा है।

यह भारत के मेक इन इंडिया इंडस्ट्रियल लक्ष्यों से मेल खाता है।

यह प्रोजेक्ट भारत को अपने समुद्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकता है,

- जहाज मरम्मत बुनियादी ढांचे
- समुद्री इंजीनियरिंग विकास
- बंदरगाह से जुड़ी औद्योगिक गतिविधि
- वैश्विक समुद्री सेवा प्रतिस्पर्धात्मकता

5. भारत के समुद्री कार्यबल के लिए कौशल विकास को बढ़ावा

इसके अलावा, शिप रिपेयर स्किल डेवलपमेंट के लिए एक खास व्यवस्था की भी घोषणा की गई।

यह वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है।

इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक मजबूत केंद्र बनाना है।

- जहाज निर्माण पेशेवर
- जहाज मरम्मत विशेषज्ञ
- समुद्री इंजीनियरिंग प्रतिभा
- औद्योगिक समुद्री सेवाएँ

यह एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किल्ड लेबर के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कॉम्पिटिटिवनेस को कम करती है।

6. भारत-यूएई एआई पार्टनरशिप: 8 एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटर क्लस्टर की घोषणा

सबसे भविष्य की घोषणाओं में से एक आठ एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटर क्लस्टर बनाने की योजना थी।

इस प्रोजेक्ट में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और G42 के बीच सहयोग शामिल होगा।

यह AI और कंप्यूटिंग में एक बड़ा माइलस्टोन होगा।

एक्साफ्लॉप स्केल कंप्यूटिंग बहुत एडवांस्ड कम्प्यूटेशनल कैपेसिटी से जुड़ी है और यह इसमें उपयोगी है,

- कृत्रिम होशियारी
- मौसम मॉडलिंग
- रक्षा सिमुलेशन
- वैज्ञानिक अनुसंधान
- बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण
- उन्नत कंप्यूटिंग नवाचार

7. UAE ने भारत में \$5 बिलियन के निवेश का वादा किया

UAE ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में \$5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी वादा किया।

इससे इन सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है,

- परिवहन बुनियादी सुविधाओं
- शहरी विकास
- रसद
- औद्योगिक विस्तार
- वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

इसके अलावा, बड़े सॉवरेन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से अक्सर लंबे समय का इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बेहतर होता है।

## राष्ट्रीय मामले

- सोमनाथ मंदिर के फिर से खुलने के 75 साल और 1026 में हुए पहले दर्ज हमले के 1000 साल पूरे होने पर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के ज़रिए पूरे देश में मनाया जाता है।
- भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजनीय यह मंदिर, सदियों से बार-बार हुए हमलों और पुनर्निर्माण के बावजूद भारत की आध्यात्मिक विरासत, मज़बूती और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है।
- सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लोगों ने मंदिर के पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार और आधुनिक विकास में अहम भूमिका निभाई। 150 फुट ऊंचे शिखर, सोने की परत चढ़े कलश और अरब सागर के सुंदर नज़ारे सहित अपनी शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर, सोमनाथ आस्था, राष्ट्रीय गौरव और सभ्यता की निरंतरता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है।
- 11 मई 2026 को, बोत्सवाना से दो मादा चीतों को भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा गया, जो वाइल्डलाइफ़ रेस्टोरेशन में एक अहम कदम है।
- जानवरों ने क्वारंटाइन और एकलीमेटाइज़ेशन पूरा कर लिया था, और 2026 की शुरुआत में लाए जाने के बाद भारत के क्लाइमेट, शिकार की जगह और जंगल के इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लिया था।
- 2022 में शुरू हुए चीतों के रीड्रोडक्शन प्रोग्राम में नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को दूसरी जगह भेजा गया है, जिससे भारत में अब शावकों समेत लगभग 57 चीते हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद
- जंगली चीतों की एक सेल्फ-सस्टेनिंग आबादी को फिर से बनाना, बायोडायवर्सिटी को मज़बूत करना और कुनो, गांधी सागर और नौरादेही जैसी सैंक्चुअरी में हैबिटेट को बढ़ाना है।
- फ्यूल बचाने और गैर-ज़रूरी विदेश यात्रा से बचने की अपील की, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिससे इकॉनमी दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों और जियोपॉलिटिकल टेंशन के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाती है। कच्चे तेल की ज़्यादा कीमतों से पेट्रोल, डीज़ल, ट्रांसपोर्ट, किराने का सामान, फ़्लाइट और रोज़ाना की ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और घरों के बजट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। गैर-ज़रूरी फ्यूल का इस्तेमाल कम करने से तेल का इंपोर्ट कम करने, फॉरिन एक्सचेंज रिज़र्व को बचाने, रुपये को सपोर्ट करने और ग्लोबल अनिश्चितता के समय में पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्मूथ ड्राइविंग और फ्यूल की बर्बादी से बचने जैसे आसान कदम पर्सनल खर्च कम कर सकते हैं और साथ ही भारत की लॉन्ग-टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेजिलिएंस को भी मज़बूत कर सकते हैं।
- धारा 498 ए पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में पूरे परिवार को झूठे आरोप में फंसाने से रोकने के साथ महिलाओं की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत पर प्रकाश डाला। अदालत ने पति के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी लेकिन ससुराल वालों के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए, यह कहते हुए कि आरोपों में विशिष्ट सबूतों का अभाव था और वे बहुत सामान्य थे। 1983 में शुरू की गई धारा 498A विवाहित महिलाओं को क्रूरता, घरेलू दुर्व्यवहार और दहेज से संबंधित उत्पीड़न से बचाती है, लेकिन अदालतों ने व्यक्तिगत जवाबदेही और सबूत आधारित जांच

के महत्व पर जोर दिया है। निर्णय इस बात पर जोर देता है कि जहां वास्तविक पीड़ितों को मज़बूत कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट सबूत पर निर्भर होनी चाहिए, जिससे पारिवारिक विवादों में निष्पक्षता और अधिक कानूनी जागरूकता को बढ़ावा मिले।

- 11 मई 2026 को, भारत ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नई दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया, जिसका मकसद खेती, न्यूट्रिशन और हेल्थकेयर को एक नेशनल स्ट्रेटेजी से जोड़ना है। यह मिशन इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च की एक मिली-जुली पहल है, जिसका फोकस भारत को बीमारी के इलाज के मॉडल से बचाव और न्यूट्रिशन पर आधारित हेल्थकेयर सिस्टम में बदलना है। यह बायो-फोर्टिफाइड फसलों, बाजरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और "खाना ही दवा" के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर कुपोषण, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, डायबिटीज और लाइफस्टाइल से जुड़ी दूसरी बीमारियों जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। इंसान, जानवर और पर्यावरण की सेहत को मिलाकर वन हेल्थ अप्रोच के ज़रिए, इस मिशन का मकसद पूरे देश में पब्लिक हेल्थ, किसानों की इनकम और सस्टेनेबल फूड सिस्टम को बेहतर बनाना है।
- भारत सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 (VB-G RAM G Act) को लागू करने की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेगा, जो ग्रामीण रोज़गार नीति में एक बड़ा बदलाव होगा।
- नए ढांचे के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों के वेतन वाले रोज़गार की कानूनी गारंटी मिलेगी, साथ ही बेरोजगारी भत्ता और मज़बूत आजीविका समर्थन तंत्र भी मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए 2026-27 के लिए लगभग ₹ 95,692 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटन है, जिसका लक्ष्य खर्च और संपत्ति निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे, नौकरी सृजन और गांव स्तर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। निरंतर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), अपग्रेड किए गए जाँव कार्ड और ग्राम पंचायतों की मज़बूत भूमिका के साथ, सुधार पारदर्शिता, तेज़ी से मजदूरी भुगतान और विकेंद्रीकृत ग्रामीण शासन पर केंद्रित है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज़िला और तालुका कोर्ट में ज्यूडिशियल रिकॉर्ड को डिजिटली इंटीग्रेट करने के लिए 'वन केस वन डेटा' पहल शुरू की। इस सुधार का मकसद एक यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम के ज़रिए केस ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटर-कोर्ट कोऑर्डिनेशन और ज्यूडिशियल जानकारी तक तेज़ी से पहुँच को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का बनाया AI-पावर्ड चैटबॉट 'सु- सहायक' भी पेश किया गया ताकि केस लड़ने वालों, वकीलों और नागरिकों को कोर्ट से जुड़ी सर्विस में मदद मिल सके। यह पहल भारत के AI-ड्रिवन ज्यूडिशियल मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़ते कदम को दिखाती है, जिससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में सुधार होता है।
- श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने 1 मई, 2026 से पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए 1% कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस नोटिफाई किया है। यह सेस ज़मीन और मुआवजे के खर्चों को छोड़कर कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें वर्कर बेनिफिट्स के लिए

- स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स द्वारा मैनेज किया जाएगा। इस पहल का मकसद इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर्स के लिए हेल्थकेयर, एजुकेशन असिस्टेंस, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। यह सुधार भारत के नए लेबर कोड का हिस्सा है, जबकि रजिस्ट्रेशन गैप और एडमिनिस्ट्रेटिव देरी के कारण लगभग ₹ 49,800 करोड़ के बिना इस्तेमाल हुए वेलफेयर फंड्स को लेकर चिंता बनी हुई है।
- सूर्यकांत ने कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और भारत के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी बनाने की घोषणा की। जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली यह हाई-पावर्ड कमेटी, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुरानी कोर्ट बिल्डिंग, डिजिटल गैप, भीडभाड़ और केस मैनेजमेंट में देरी जैसी समस्याओं को हल करने के लिए एक नेशनल रोडमैप तैयार करेगी। मुख्य फोकस एरिया में ई-कोर्ट्स पहल को मजबूत करना, डिजिटल फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, केस ट्रैकिंग सिस्टम को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी वाले, नागरिकों के अनुकूल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना शामिल है। इस सुधार का मकसद ज्यूडिशियल एफिशिएंसी में सुधार करना, केस बैकलॉग को कम करना और लिटिगेंट और वकीलों के लिए बेहतर सुविधाएं देना है, क्योंकि भारत एक ज़्यादा मॉडर्न और आसान ज्यूडिशियरी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है।
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अहमदाबाद (सरखेज) -धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना भारत का पहला सेमी हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मंजूर हुए ₹ 20,667 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से रेलवे नेटवर्क में करीब 134 km और जुड़ जाएंगे और इसके FY 2030-31 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, आने वाले धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत प्लान किए गए इस प्रोजेक्ट से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, रीजनल इकोनॉमिक एक्सपेंशन, रोजगार पैदा करने और भारत के आत्मनिर्भर भारत विज़न को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
- नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ₹ 37,500 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी है। इस पहल का मकसद लगभग 75 मिलियन टन कोयले और लिग्नाइट को गैसीफाई करना है और यह 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसीफिकेशन हासिल करने के भारत के बड़े लक्ष्य में मदद करता है। कोल गैसीफिकेशन कोयले को सिनगैस (सिंथेसिस गैस) में बदलता है, जिसका इस्तेमाल मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG), और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे भारत की इम्पोर्ट पर भारी निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। यह स्कीम प्लांट और मशीनरी की लागत का 20% तक का इंसेंटिव देती है, साथ ही 30 साल के कोल लिंकेज सपोर्ट के साथ, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विज़न के तहत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है।
- पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LEADS 2025 रिपोर्ट जारी करते और LEAPS 2025 पुरस्कार प्रदान करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान

निर्यात में 1 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। भू-राजनीतिक तनाव, धीमी आर्थिक वृद्धि और व्यापार अनिश्चितताओं जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात में ऐतिहासिक 863 बिलियन डॉलर दर्ज किया, जबकि सेवाओं के निर्यात में लगभग 8.5-9% की वृद्धि हुई। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का अब 38 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से व्यापार कवरेज है, जिसमें जीसीसी, कनाडा, मैक्सिको और मर्कोसुर जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए चल रही बातचीत शामिल है। LEADS 2025 रिपोर्ट ने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली सहित शीर्ष लॉजिस्टिक्स कलाकारों को मान्यता दी

- DGFT (मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के अनुसार, भारत ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी एक्सपोर्ट पर तुरंत बैन लगा दिया है, जिससे पॉलिसे "रिस्ट्रिक्टेड" से "प्रोहिबिटेड" हो गई है। यह बैन कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी पर लागू होता है, जिसका मकसद घरेलू सप्लाई में स्थिरता सुनिश्चित करना और महंगाई के जोखिमों को कंट्रोल करना है। पहले से ट्रांज़िट में या पहले से क्लियर शिपमेंट के लिए सीमित छूट लागू है, और सरकारी मंजूरी और टैरिफ कोटा (EU, US) के तहत कुछ खास एक्सपोर्ट जारी रहेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर भारत, कम क्लोजिंग स्टॉक और बढ़ते फूड महंगाई के दबाव की चिंताओं के साथ, कड़े घरेलू वेलेंस अनुमानों का सामना कर रहा है।
- भारत का इथेनॉल कार्यक्रम एक प्रमुख संक्रमण चरण में प्रवेश कर गया है क्योंकि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 की पहली छमाही के दौरान मक्का पहली बार देश का सबसे बड़ा इथेनॉल फीडस्टॉक के रूप में उभरा है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन द्वारा संकलित अनुमानों के अनुसार, मक्के ने लगभग 182 करोड़ लीटर इथेनॉल का योगदान दिया, जो कि अधिशेष चावल और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे अन्य फीडस्टॉक से आगे निकल गया। भारत की संचयी इथेनॉल आपूर्ति ईएसवाई 2025-26 के पहले छह महीनों में 515 करोड़ लीटर को पार कर गई, जो देश के स्वच्छ ईंधन और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में मजबूत गति को दर्शाती है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि मक्का पसंदीदा फीडस्टॉक बन रहा है क्योंकि यह साल भर उपलब्धता, गन्ने की तुलना में कम पानी की खपत और E20 से परे उच्च इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों के लिए बेहतर दीर्घकालिक मापनीयता प्रदान करता है।



- भोपाल में लगा "एल्ली ट्री" कोई असली पेड़ नहीं है, बल्कि एक सोलर-पावर्ड बायो-इंजीनियरिंग डिवाइस है जो माइक्रोएल्ली का इस्तेमाल करके CO<sub>2</sub> सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दावा है कि यह 25 नेचुरल पेड़ों की तरह काम करता है, जिससे शहरी इलाकों में प्रदूषण कम होता है। यह एक लिक्विड, वर्टिकल एयर-प्यूरिफाइंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिसे उन शहरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ पेड़ लगाने के लिए जगह कम है। डेवलपर्स का कहना है कि यह हवा की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है और लोकल लेवल पर पार्टिकुलेट मैटर को कम कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक सप्लीमेंट है, असली जंगलों का रिप्लेसमेंट नहीं। कुल मिलाकर, यह एक ग्रीन-टेक इनोवेशन है, न कि कोई असली पेड़, जिसका मकसद शहरी हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है।
- भारत 2026 के होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बाद वैश्विक तेल और एलएनजी प्रवाह को बाधित करने के बाद दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ओमान को गुजरात से जोड़ने वाली ₹ 40,000 करोड़ की सबसे गैस पाइपलाइन की योजना बना रहा है। प्रस्तावित 2,000 किलोमीटर की गहरे समुद्र की पाइपलाइन होर्मुज जलडमरूमध्य के कमजोर मार्ग को बायपास करेगी और सीधे ओमान से भारत तक प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी। इस परियोजना को मंजूरी के बाद 5-7 साल लगने की उम्मीद है और यह 2033 से 2035 के बीच चालू हो सकती है। इसमें शामिल प्रमुख भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में गेल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शामिल हैं। गेल व्यवहार्यता योजना और पाइपलाइन संचालन का नेतृत्व करेगा। यह कदम भारत द्वारा होर्मुज व्यवधान के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के बाद उठाया गया है,
- इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 से पहले सासन गिर में लायन स्पीशीज़ स्पॉटलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में एजुकेशनल इवेंट्स, फिल्मों और एक्सपर्ट डिस्कशन के ज़रिए बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन, शेरों की सुरक्षा और शेरों वाले देशों के बीच इंटरनेशनल सहयोग के लिए भारत के कमिटीमेंट को हाईलाइट किया गया। भूपेंद्र पटेल ने गिर को एक ऐसा मॉडल बताया जहाँ वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मज़बूत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ सफलतापूर्वक साथ-साथ चलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2025 में 891 तक पहुँच गई, जो 2020 से 32% की बढ़ोतरी दिखाती है, जिससे यह दुनिया भर में कंज़र्वेशन की एक बड़ी सफलता की कहानी बन गई है।
- भारत 1-2 जून, 2026 को नई दिल्ली में पहला IBCA समिट होस्ट करेगा। यह अलायंस शेर, बाघ, तेंदुए, स्रो लेपर्ड, चीते, जगुआर और प्यूमा सहित सात मुख्य बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को बचाने पर फोकस करता है। सरकार का प्रोजेक्ट लायन, जो 2020 में लॉन्च किया गया था, एशियाई शेरों के लंबे समय तक जीवित रहने को पक्का करने के लिए हैबिटेट बढ़ाने, साइंटिफिक मॉनिटरिंग और इकोलॉजिकल मजबूती को सपोर्ट करता है।
- भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है, जिसके तहत लगभग 36.73 करोड़

मतदाता शामिल होंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घर-घर सत्यापन, नए मतदाताओं को जोड़ने, डुप्लिकेट को हटाने और रिकॉर्ड में सुधार के माध्यम से सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगभग 3.94 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) शामिल हैं, जो क्षेत्र सत्यापन करेंगे और राजनीतिक निगरानी सुनिश्चित करेंगे। प्रमुख चरणों में मसौदा रोल प्रकाशन, दावे और आपत्तियां, और जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच अंतिम मतदाता सूची जारी करना शामिल है। बड़े पैमाने पर किए जाने वाले इस अभ्यास में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, झारखंड,

- केंद्र ने मिजोरम अदरक को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रीमियम उत्पाद में बदलने के लिए ₹ 189.79 करोड़ का मिजोरम अदरक मिशन शुरू किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित यह मिशन किसानों की आय वृद्धि, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे, निर्यात की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर केंद्रित है। इस पहल का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया और लालदुहोमा ने किया। मिजो अदरक अपने 6-8% ओलियोरेसिन सामग्री के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो वैश्विक औसत से बहुत अधिक है, जो इसे खाद्य, फार्मा, सौंदर्य प्रसाधन और हर्बल उद्योगों के लिए मूल्यवान बनाता है। मिशन चार स्तंभों - मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार एकीकरण और अभिसरण पर बनाया गया है - और लगभग 20,000 कृषक परिवारों को जोड़ते हुए प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा।
- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्टिस फ़ाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया है ताकि गांव की महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के मौके बढ़ाए जा सकें। इस पहल का मकसद इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस और जॉब प्लेसमेंट में मदद देना है ताकि महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। इस प्रोग्राम के तहत, पूरे भारत में 12 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जो 6,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों को जॉब दिलाने में मदद करते हैं, जिसमें लगभग 80% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। प्रोजेक्ट सक्षम नेशनल हाईवे के पास रहने वाले समुदायों के लिए आर्थिक मौके बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लोकल रोजी-रोटी से भी जोड़ता है।
- नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 को यूनाइटेड अरब अमीरात गए, जहाँ दोनों देशों ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बड़े एग्रीमेंट साइन किए। इसका एक अहम नतीजा इंडियन स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व पार्टनरशिप थी, जिससे भारत में 30 मिलियन बैरल तक ADNOC कूड ऑयल स्टोर करने की इजाज़त मिली। इस कोऑपरेशन में विशाखापत्तनम में फैसिलिटी और ओडिशा में प्रपोज़्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ फुजैरा में पॉसिबल रेसिप्रोकल स्टोरेज शामिल है। दोनों देशों ने एक लॉन्ग-टर्म LPG सप्लाई एग्रीमेंट पर भी साइन किया, जिसका मकसद बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल एनर्जी अनसर्टेनिटी के बीच स्टेबल फ्यूल अवेलेबिलिटी पक्का करना है।

समाचार में राज्य

- वारंगल में भारत के पहले चालू PM MITRA पार्क का उद्घाटन किया , जिसे भारत के टेक्सटाइल मैनुफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ₹ 1,695 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। 1,327 एकड़ में फैले इस पार्क से ₹ 6,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने और लगभग 24,400 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। PM MITRA स्कीम के तहत बना यह प्रोजेक्ट सरकार के 5F विज़न — फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरिन — को फॉलो करता है, जो पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही जगह पर इंटीग्रेट करता है। मजबूत कनेक्टिविटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टर सपोर्ट के साथ, वारंगल एक बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, मैनुफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रहा है।
- 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली , जिससे राज्य के राजनीतिक माहौल में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। उनकी पार्टी, तमिलनाडु वेत्ती कडगम, 2026 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK, और IUML जैसी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। विजय की जीत ने तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कडगम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम के लगभग छह दशकों के दबदबे को खत्म कर दिया। सिनेमा के सुपरस्टार से मुख्यमंत्री तक उनका उदय तमिलनाडु में फिल्मी हस्तियों के राजनीति में आने की लंबी परंपरा को दिखाता है , जैसे एमजी रामचंद्रन और जे. जयललिता जैसे नेता।
- सुबेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली , और BJP ने नई राज्य सरकार बनाई। कैबिनेट में दिलीप घोष , अग्निमित्रा पॉल , निस्थि प्रमाणिक और दूसरे लोग शामिल हैं जो पंचायत, कल्याण और विकास जैसे ज़रूरी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। खबर है कि नबन्ना में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत रोलआउट, BSF लैंड ट्रांसफर और नौकरी की उम्र में छूट के उपायों को मंजूरी दी गई। TMC के दबदबे के बाद इस बदलाव को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो 2026 में राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के मुताबिक पश्चिम बंगाल की शासन की प्राथमिकताओं को बदल रहा है।

- हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली , जो 2016 के बाद से NDA सरकार की लगातार तीसरी जीत है। गुवाहाटी में हुए भव्य समारोह में PM नरेंद्र मोदी , केंद्रीय मंत्री और कई BJP-NDA मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए। उनके साथ, रामेश्वर तेली , अतुल बोरा , चरण बोरो और अजंता नियोग ने नए कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। NDA गठबंधन ने असम विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि रणजीत कुमार दास को नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।
- कर्नाटक ने 2026-27 एकेडमिक ईयर से सरकारी इंस्टीट्यूशन में अटेंडेंस ट्रैकिंग को मॉडर्न बनाने के लिए कर्तव्य-KAAMS ऐप (कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम) शुरू किया है। यह सिस्टम ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह AI-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन , जियो-फेंसिंग और HRMS इंटीग्रेशन लाता है ताकि टीचर, हेडमास्टर और स्टाफ के लिए वर्कफोर्स की सही और ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग पक्की हो सके। डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस द्वारा डेवलप किया गया यह ऐप एम्प्लॉई को रोज़ाना "इन टाइम" और "आउट टाइम" अटेंडेंस मार्क करने के लिए कहता है और यह HRMS और स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसे सिस्टम से लिंक होता है। इस रोलआउट का मकसद 20 लाख से ज्यादा सरकारी एम्प्लॉई को कवर करना है , जिससे कर्नाटक के पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल गवर्नेंस में सुधार होगा।
- शिवाजीनगर इलाके में भारत का पहला लो एमिशन जोन (LEZ) बनाने जा रहा है , जो शहरी एयर क्वालिटी कंट्रोल और सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह प्रोजेक्ट पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ITDP इंडिया के सपोर्ट से बना रहा है और यह महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 के हिसाब से है ताकि क्लीनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। LEZ, पुणे के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के लगभग 7-10% हिस्से में ज्यादा एमिशन वाली गाड़ियों, खासकर भारत स्टेज-III नॉर्म्स से कम पुरानी गाड़ियों और 2011 से पहले के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाएगा या रेगुलेट करेगा, और इसके लिए पॉल्यूशन चार्ज और पेनल्टी का इस्तेमाल करेगा। इसे लागू करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
- राजस्थान ने यशोदा मदर्स कार्यक्रम और राज्य द्वारा संचालित मानव दूध बैंकों के माध्यम से नवजात पोषण और स्तन दूध दान पहल का विस्तार किया है ताकि उन शिशुओं का समर्थन किया जा सके, जिनकी मातृ स्तन दूध तक पहुंच नहीं है। इस पहल में बाडमेर जिला अस्पताल में मदर मिल्क बैंक , जीवन धारा मिल्क बैंक और आंचल मदर मिल्क बैंक जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल हैं , जो नवजात देखभाल के लिए दान किए गए स्तन दूध को एकत्रित, जांच और सुरक्षित रूप से संग्रहित करती हैं। ये मानव दूध बैंक संक्रमण स्क्रीनिंग (एचआईवी परीक्षण) और नियंत्रित तापमान (लगभग -19 डिग्री सेल्सियस) पर भंडारण सहित सख्त चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, एनआईसीयू में नवजात शिशुओं को सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करते हैं और शिशु मृत्यु दर को कम करते हैं। नॉर्वे-भारत भागीदारी पहल के तहत समर्थित कार्यक्रम , स्तनपान कराने वाली माताओं को "यशोदा माताओं" के रूप में बढ़ावा देता



- केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में AINRC की अगुवाई वाले NDA गठबंधन की जीत के बाद, एन. रंगासामी ने 13 मई 2026 को रिकॉर्ड पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। के. कैलाशनाथन ने पद की शपथ दिलाई, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में NDA का शासन जारी रहने का पता चला। मुख्यमंत्री के साथ, मल्लाडी कृष्ण राव और ए. नमस्सिवयम ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली, जो कैबिनेट में AINRC और BJP के बीच गठबंधन के बैलेंस को दिखाता है। चुनाव के नतीजे, जिसमें NDA ने सत्ता बरकरार रखी, ने पुडुचेरी के सबसे असरदार राजनीतिक नेताओं में से एक के रूप में रंगासामी की स्थिति को और मजबूत किया है और इस क्षेत्र में गठबंधन के लगातार जनादेश को दिखाता है।
- यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत मिलने के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केरल में नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए बीडी सतीशन को चुना है। इस घोषणा से केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नियला जैसे सीनियर नेताओं से जुड़े नेतृत्व के कई दिनों से चल रहे कयासों का अंत हो गया है। खबर है कि UDF ने 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 102 सीटें जीतीं, पिनारै विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हराया और राज्य में एक दशक के लेफ्ट शासन का अंत किया। एक प्रैक्टिसिंग वकील और परावुर से छह बार के MLA, सतीशन पहले विपक्ष के नेता के रूप में काम कर चुके हैं और अब पहली बार केरल के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
- हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे 26 मई को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार, लिब-इन रिलेशनशिप, अनिवार्य विवाह पंजीकरण और तलाक पंजीकरण जैसे मामलों को कवर करने वाला एक सामान्य नागरिक ढांचा तैयार करना है। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य नागरिक कानूनों के एक सामान्य समूह से है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है, जो कुछ नागरिक मामलों में धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेता है। असम सरकार ने कहा कि यह कदम कानूनी एकरूपता, कानून के समक्ष समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। राज्य ने स्पष्ट किया है कि जनजातीय समुदायों, धार्मिक अनुष्ठानों, पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रस्तावित कानून से छूट दी जाएगी। असम अब राज्य-स्तरीय यूसीसी कार्यान्वयन के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने में गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में शामिल हो गया है।
- विनय कुमार सक्सेना ने माहे का उद्घाटन किया लद्दाख के ऊंचाई वाले चांगथांग इलाके में टोकपो-राल्धो सिंचाई नहर। 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी यह 2.10 km लंबी नहर याया झील से माहे के खेतों तक पानी ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे भारत के सबसे मुश्किल और दूर-दराज के इलाकों में से एक में सिंचाई बेहतर होगी। इस प्रोजेक्ट से लगभग 100 एकड़ खेती की ज़मीन को फ़ायदा होने की उम्मीद है, जिससे उन किसानों को मदद मिलेगी जो पहले मौसमी ग्लेशियर पिघलने और पानी के ऐसे सोर्स पर निर्भर थे जिनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इसका पूरा होना हिमालय की मुश्किल परिस्थितियों में एक बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी है, जिसमें कम ऑक्सीजन, जमा देने वाले तापमान और मुश्किल इलाके को झेलने के लिए मज़बूत स्ट्रक्चर हैं। उद्घाटन के साथ ही, मिट्टी बचाने, ढलान को स्थिर रखने और नाजुक चांगथांग इकोसिस्टम को ठीक करने में मदद के लिए 15,000 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया।
- रथिंद्र बोस 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिना किसी विरोध के चुने गए। वे आज़ादी के बाद के इतिहास में इस पद पर बैठने वाले उत्तर बंगाल के पहले विधायक बने। विधानसभा में उनके नाम का प्रस्ताव सुवेदु अधिकारी ने रखा, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर तपस रॉय ने वॉयस वोट किया। सभी 207 BJP विधायकों ने बोस की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद 294 सदस्यों वाली विधानसभा में BJP की मज़बूत बहुमत के कारण कूच बिहार दक्षिण से MLA बोस के जीतने की पूरी उम्मीद थी। उनकी नियुक्ति को उत्तर बंगाल के लिए एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, यह एक ऐसा इलाका है जो राज्य में BJP के लिए एक अहम सपोर्ट बेस बन गया है।
- भिवाड़ी में अपना पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर लॉन्च किया, जिससे राज्य भारत के तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में शामिल हो गया। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन भजन लाल शर्मा ने किया, जबकि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्लस्टर में पहले ही लगभग ₹ 1,200 करोड़ का निवेश आ चुका है और इससे लगभग 2,500 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर AI, स्मार्टफोन, EVs, टेलीकॉम और डिफेंस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पहल राजस्थान के बड़े "डेवलपड राजस्थान 2047" विज़न को सपोर्ट करती है और इसके एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करती है।

### अंतरराष्ट्रीय मामले

- भारत 31 मई को नई दिल्ली में चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट 2026 की मेज़बानी करेगा, जिसमें अफ्रीकी नेता ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थकेयर और क्लाइमेट एक्शन में सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक साथ आएंगे। यह समिट
- अफ्रीका के साथ भारत की बढ़ती पार्टनरशिप पर ज़ोर देगा, जिसमें विज़न 2047 और एजेंडा 2063 के तहत आर्थिक संबंधों, डिजिटल सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी पर फ़ोकस किया जाएगा।
- अभी इंडिया-अफ्रीका ट्रेड लगभग \$85 बिलियन का है, जिसमें इंडिया लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कई सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट के
- ज़रिए अफ्रीकी देशों को सपोर्ट करता है। यह इवेंट साउथ-साउथ सहयोग, क्लाइमेट जस्टिस और कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा देगा, जिससे ग्लोबल साउथ में इंडिया-अफ्रीका पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल अहमियत और मज़बूत होगी।

- सऊदी अरब, इंटरनेशनल विग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के तौर पर शामिल होने वाला है। इससे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा के लिए भारत की अगुवाई वाली ग्लोबल कोशिशों को मज़बूती मिलेगी। भारत द्वारा शुरू किया गया यह अलायंस, इंटरनेशनल सहयोग और हैबिटेट संरक्षण के जरिए बाघ, शेर, तेंदुए, चीते, जगुआर, प्यूमा और स्नो लेपर्ड सहित सात मुख्य बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की सुरक्षा पर फोकस करता है। IBCA में अभी 25 सदस्य देश और 5 ऑब्ज़र्वर देश शामिल हैं, जो रिसर्च, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंस और अलग-अलग इलाकों में वाइल्डलाइफ सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। सऊदी अरब के शामिल होने से फ़ाइनेंशियल मदद, रीजनल पार्टनरशिप और कंज़र्वेशन डिप्लोमेसी बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही ग्लोबल एनवायरनमेंटल और वाइल्डलाइफ पहलों में भारत की बढ़ती लीडरशिप को भी मज़बूती मिलेगी।
- शहबाज़ शरीफ़ ने घोषणा की कि 10 मई को हर साल "मरका-ए-हक़ दिवस" के रूप में मनाया जाएगा, जिसका मतलब है "सच के लिए लड़ाई" या "न्याय के लिए लड़ाई", जो पाकिस्तान में राष्ट्रीय गौरव, एकता और राजनीतिक पहचान के विषयों पर प्रकाश डालता है। ऐसे प्रतीकात्मक राष्ट्रीय समारोह अक्सर सामूहिक स्मृति, देशभक्ति और राजनीतिक कहानियों को मज़बूत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, खासकर क्षेत्रीय तनाव और भू-राजनीतिक संवेदनशीलता के समय में। यह घोषणा भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच हुई है, जहाँ प्रतीकवाद और ऐतिहासिक कहानियाँ अक्सर दक्षिण एशिया में जनता की राय, मीडिया बहस और कूटनीतिक संदेशों को प्रभावित करती हैं। यह विकास दिखाता है कि कैसे प्रतीकात्मक राजनीति राष्ट्रीय पहचान, भावनात्मक सार्वजनिक चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को आकार दे सकती है, यहाँ तक कि सरकारी नीतियों या क्षेत्रीय संबंधों को सीधे बदले बिना भी।
- केविन वार्श को US सीनेट ने फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में 14 साल के टर्म के लिए कन्फर्म कर दिया है, जिससे वे फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन बन सकते हैं। सीनेट ने 51-45 वोटों से उनके नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी, जबकि फेड चेयरमैन के तौर पर जेरोम पावेल की जगह ऑफिशियली लेने के लिए अभी भी एक अलग कन्फर्मेशन वोट की जरूरत है। वार्श ने पहले 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फेडरल रिजर्व में काम किया था और उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी, महंगाई कंट्रोल और फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म पर एक असरदार आवाज माना जाता है। उनका अपॉइंटमेंट ऐसे अहम समय पर हुआ है जब US इकोनॉमी महंगाई के दबाव, इंटररेट रेट्स पर पॉलिटिकल जांच और ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता का सामना कर रही है, जिससे फेड लीडरशिप ट्रांजिशन पर दुनिया भर में करीब से नजर रखी जा रही है।
- BRICS विदेश मंत्रियों की मीटिंग 2026, 14 मई को नई दिल्ली में शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता एस. जयशंकर ने की, जो भारत की BRICS चेयरमैनशिप 2026 से एक ज़रूरी कदम है। दो दिन की मीटिंग में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मल्टीलेटरल रिफॉर्म पर चर्चा शामिल है। इसका एक मुख्य फोकस BRICS@20 है, जिसमें ग्रुप के 20 साल

- के माइलस्टोन तक पहुंचने पर रेजिलिएंस, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़ोर दिया जाएगा। नेताओं ने UN और फाइनेंशियल सिस्टम जैसे ग्लोबल गवर्नंस इंस्टीट्यूट्स में रिफॉर्म पर भी चर्चा की ताकि डेवलपिंग देशों के लिए रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। यह इवेंट नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत ग्लोबल साउथ लीडरशिप और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।
- सातवें कार्यकाल के लिए शपथ ली है, जो आधुनिक अफ्रीकी इतिहास में सबसे लंबे राजनीतिक कार्यकालों में से एक है। 81 वर्षीय नेता, जो पहली बार 1986 में सत्ता में आए थे, ने युगांडा के चुनाव आयोग के अनुसार, जनवरी 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में 71.65% वोट के साथ जीत हासिल करने के बाद राजधानी कंपाला में शपथ ली। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी बोबी वाइन को 24.72% वोट मिले। समर्थक मुसेवेनी को युगांडा को स्थिर करने, बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का श्रेय देते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि उनके लंबे शासन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। मुसेवेनी की निरंतर अध्यक्षता संवैधानिक संशोधनों द्वारा सक्षम हुई, जिसने राष्ट्रपति पद की सीमा और आयु प्रतिबंध दोनों को हटा दिया,
  - अफ़गानिस्तान में तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने देश भर में कस्टम लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारतीय कंपनी TCRC के साथ \$46 मिलियन का एग्रीमेंट किया है। पांच साल के इस प्रोजेक्ट में काबुल में लैबोरेटरी सेंटर और नौ कस्टम फैसिलिटी बनाई जाएंगी, साथ ही एडवांस्ड टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे और मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद अफ़गानिस्तान के ट्रेड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना है। यह अफ़गानिस्तान स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी अथॉरिटी को भी मजबूत करेगा, जिससे एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में मदद मिलेगी और देश की ट्रेड क्रेडिबिलिटी में सुधार होगा। इस एग्रीमेंट में अफ़गान टेक्निकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, विदेशी एक्सपर्ट्स के साथ कोलेबोरेशन और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पाने की कोशिशें शामिल हैं। भारत के लिए, यह डील प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के जरिए अफ़गानिस्तान के साथ लगातार इकोनॉमिक एंगेजमेंट को दिखाती है, जबकि अफ़गानिस्तान के लिए यह लॉन्ग-टर्म ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है।
  - टोक्यो में आयोजित कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट (CCRA) मीटिंग में लिए गए निर्णय के बाद, भारत ने 2026-28 के कार्यकाल के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। यह कदम वैश्विक साइबर सुरक्षा और IT सुरक्षा मानकों को आकार देने में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड वह तकनीकी निकाय है जो IT उत्पादों की सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास और अद्यतन करता है। यह कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का समर्थन करता है, जो एक वैश्विक समझौता है जो सदस्य देशों को साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता देने की अनुमति देता है, जिससे राष्ट्रों के बीच बार-बार परीक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है। भारत 2013 से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके प्रमाणन निकाय STQC निदेशालय के माध्यम से CCRA का हिस्सा रहा है।

- यूरोपीय संघ (यूरोपीय संघ) ने समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र देशों की अपनी अद्यतन सूची में भारत को शामिल किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात सितंबर 2026 के बाद भी जारी रहेगा। यह निर्णय संभावित व्यापार व्यवधान को रोकता है और उच्च मूल्य वाले वैश्विक बाजार तक भारत की पहुंच को मजबूत करता है, क्योंकि यूरोपीय संघ भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग 19% है। इससे पहले, भारत ने रोगाणुरोधी अवशेषों और अनुपालन मानकों पर सख्त यूरोपीय संघ के मानदंडों के कारण बहिष्कार का जोखिम उठाया था, लेकिन बेहतर निगरानी प्रणाली और खाद्य सुरक्षा अनुपालन का प्रदर्शन करने के बाद इसे बनाए रखा गया था। यह अनुमोदन भारत के निर्यात गुणवत्ता ढांचे में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। भारत का समुद्री निर्यात वित्त वर्ष 2026 में लगभग 8.43 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल लगभग 14% बढ़ रहा है, जिससे समुद्री भोजन देश की निर्यात अर्थव्यवस्था और तटीय आजीविका में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है।
- लेटेस्ट हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट 78वीं पोजीशन पर आ गया है, जो इसकी पिछली रैंक 75 से तीन पायदान नीचे है। इंडेक्स के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के पास अभी वीजा-फ्री, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-वीजा सुविधाओं के ज़रिए 56 जगहों तक एक्सेस है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेटा-बेस्ड रैंकिंग ट्रेवल फ्रीडम के आधार पर ग्लोबल पासपोर्ट को इवैल्यूएट करती है। हाल की गिरावट के बावजूद, भारत की लॉन्ग-टर्म पोजीशन 2021 में 90वीं रैंक और 2025 में 85वीं रैंक से बेहतर हुई है, जो ग्लोबल मोबिलिटी में धीरे-धीरे हो रही प्रोग्रेस को दिखाता है।
- भारतीय यात्रियों को भूटान, नेपाल, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में आसानी से जाने का मौका मिल रहा है। इस बीच, सिंगापुर

- ने 192 जगहों तक पहुंच के साथ दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट रैंकिंग बनाए रखी है।
- भारत ने पीयूष गोयल की लीडरशिप में मुंबई में किम्बर्ले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 को सफलतापूर्वक होस्ट किया, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और एथिकल डायमंड ट्रेड पर फोकस किया गया। मीटिंग में किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) को मजबूत करने और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को ग्लोबल मार्केट में आने से रोकने के लिए सरकारें, इंडस्ट्री लीडर और सिविल सोसाइटी एक साथ आए। भारत ने अपने 3C विज़न — क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस — को बढ़ावा दिया, साथ ही जिम्मेदार सोर्सिंग और मॉनिटरिंग सुधारों पर जोर दिया। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब के तौर पर, भारत ने ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री में अपनी लीडरशिप भूमिका को मजबूत किया और नई दिल्ली में होने वाले KP प्लेनरी में आगे की चर्चाओं की नींव रखी।
- डोनाल्ड ट्रंप चीन गए और बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ हाई-लेवल बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस बातचीत को “ऐतिहासिक” और “सफल” बताया। इस समिट में ट्रेड, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और मार्केट एक्सेस पर फोकस किया गया, हालांकि किसी भी बड़े फॉर्मल एग्रीमेंट की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया कि चीन 200 बिलियन डॉलर एयरक्राफ्ट और अरबों डॉलर के अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन बीजिंग ने इन घोषणाओं को पब्लिकली वेरिफाई नहीं किया। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और AI सेफ्टी चर्चा के मुख्य एरिया थे, जिसमें एलन मस्क और जेन्सेन हुआंग जैसे बिजनेस लीडर्स ने हिस्सा लिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लिए US-चीन संबंधों की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर ज़ोर दिया गया।

### हस्ताक्षरित समझौते/समझौता ज्ञापन

- इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने साइबर फ्रॉड को रोकने और भारत के बैंकिंग सिस्टम में म्यूल अकाउंट्स के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ एक MoU साइन किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद फ्रॉड-रिस्क इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाना, एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और रियल टाइम में संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का पता लगाने के लिए AI-ड्रिवन सिस्टम का इस्तेमाल करना है। म्यूल अकाउंट्स, जिनका

इस्तेमाल अक्सर ऑनलाइन स्कैम, फ्रिशिंग अटैक और मनी लॉन्ड्रिंग में होता है, साइबर क्राइम और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को कंट्रोल करने में एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। यह पहल I4C सस्पेक्ट रजिस्ट्री से डेटा को इंटीग्रेट करेगी और फ्रॉड वाले अकाउंट्स को जल्दी से पहचानने और ब्लॉक करने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगी, जिससे भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में सिक्योरिटी बेहतर होगी।

### पुस्तकें और लेखक

- शिवराज सिंह चौहान ने अपनी आने वाली किताब 'अपनापन' की घोषणा की है, जो नरेंद्र मोदी के साथ उनके 35 साल के जुड़ाव पर आधारित है। यह किताब PM मोदी के लीडरशिप स्टाइल, गवर्नेंस के तरीके, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और पर्सनल वैल्यूज़ के बारे में पर्सनल जानकारी देगी। चौहान के अनुसार, यह किताब सिर्फ एक पॉलिटिकल यादों से कहीं ज़्यादा है और इसमें ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिटिक्स, राज्य गवर्नेंस और नेशनल लीडरशिप के अनुभव दिखाए गए हैं। एक ज़रूरी हिस्सा 1991 की एकता यात्रा की याद दिलाता है, जहाँ चौहान कहते

हैं कि मोदी ने इस आंदोलन को युवाओं में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति जगाने के मिशन के तौर पर देखा था। किताब में मोदी की स्ट्रेटेजिक सोच, टेक्नोलॉजी से चलने वाला गवर्नेंस, अनुशासन और नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति इमोशनल सेंसिटिविटी जैसी खूबियों पर भी ज़ोर दिया गया है। 'अपनापन' का ऑफिशियल लॉन्च 26 मई, 2026 को NASC कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में एम. वेंकैया नायडू और HD देवेगौडा जैसे नेताओं की मौजूदगी में होगा।

**बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार**

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश कोषों की लॉन्च प्रक्रिया में तेजी लाने और भारत के तेजी से बढ़ते निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लिए गरुड़ प्रणाली (ग्रीन-चैनल: दस्तावेज़ स्वीकृति पर एआईएफ रोलआउट) नामक एक प्रमुख सुधार का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में, एआईएफ योजनाएं प्लेसमेंट ज्ञापन दाखिल करने के बाद लगभग 30 दिन का समय लेती हैं, लेकिन गरुड़ के तहत, पात्र योजनाएं केवल 10 कार्य दिवसों में लॉन्च हो सकती हैं, जिससे पूंजी परिणियोजन की गति और दक्षता में काफी सुधार होता है। सुधार मान्यता प्राप्त निवेशक-केवल फंड और एंजेल फंड के लिए प्रक्रियाओं को सरल करता है, जिससे प्रत्यक्ष फाइलिंग और कम अनुपालन आवश्यकताओं की अनुमति मिलती है जबकि समीक्षा के बाद जांच के माध्यम से नियामक निरीक्षण बनाए रखा जाता है। एआईएफ प्रतिबद्धताओं के 15.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने के साथ, सेबी के प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के वैकल्पिक निवेश बाजार को मजबूत करते हुए स्टार्टअप, निजी इक्विटी, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और निवेशक विश्वास को बढ़ावा देना
- BSE ने फोकस्ड IT इंडेक्स पर F&O कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे यह भारत का पहला एक्सचेंज बन गया है जो ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए IT सेक्टर-स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स ऑफर करता है। यह इंडेक्स 14 बड़ी IT कंपनियों को ट्रेक करता है और इसका मकसद करेसी में उतार-चढ़ाव और AI-ड्रिवन ट्रेड्स जैसे ग्लोबल फैक्टर्स के बीच रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। लॉन्च के दिन, इसमें 172 पार्टिसिपेंट्स और लगभग ₹ 148 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया, जिससे इन्वेस्टर्स की मजबूत दिलचस्पी दिखती है। यह प्रोडक्ट सेक्टरल ट्रेडिंग को इनेबल करता है, प्राइस डिस्कवरी को बढ़ाता है, और वोलाटाइल IT सेक्टर में इन्स्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो हेजिंग को सपोर्ट करता है।
- डिफेंस, सिविल एविएशन और एनर्जी सेक्टर में बड़े विस्तार की घोषणा की है, जिसमें फाइटर जेट इंजन और न्यूक्लियर पावर सॉल्यूशन शामिल हैं, जो भारत के इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर के साथ तालमेल बिठाता है। मॉडर्नाइजेशन के लक्ष्य। डिफेंस में, कंपनी भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के प्रोग्राम, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) को सपोर्ट करने के लिए 120 kN-क्लास नेक्स्ट-जेनरेशन फाइटर इंजन को को-डेवलप करने की योजना बना रही है, साथ ही डीप लोकलाइजेशन और पोर्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी। यह विस्तार भारतीय सप्लाय चैन को मजबूत करने, लोकल मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल एनर्जी सॉल्यूशंस की खोज करते हुए, एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए सपोर्ट बढ़ाने पर भी फोकस करता है।
- मूडीज़ रेटिंग्स ने कम खपत, धीमे इन्वेस्टमेंट, घटती इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट का हवाला देते हुए 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6% कर दिया है। मूडीज़ ग्लोबल मैक्रो आउटलुक मई 2026 अपडेट के अनुसार, 2026 और 2027 दोनों के लिए ग्रोथ अनुमानों को नीचे की ओर बदला गया, जो भारत की महामारी के बाद मजबूत रिकवरी के बाद नरमी का संकेत

देता है। एक बड़ी चिंता यह है कि भारत की इम्पोर्टेड एनर्जी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल सप्लाय में रुकावटों से महंगाई, सरकारी खर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं। मूडीज़ ने यह भी चेतावनी दी है कि जियोपॉलिटिकल तनाव, ग्लोबल शिपिंग जोखिम और एनर्जी सप्लाय की अनिश्चितताएं भारत के इन्वेस्टमेंट माहौल, कॉर्पोरेट मुनाफे और कुल मिलाकर आर्थिक विकास की गति पर असर डाल सकती हैं।

- हाल के डेटा ट्रेड के अनुसार, भारत की CPI-आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2026 में थोड़ी बढ़कर 3.48% हो गई, जो मार्च में 3.4% थी, जो मुख्य रूप से अधिक खाद्य कीमतों के कारण हुई। वृद्धि के बावजूद, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4% लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, हालांकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर भारतीय रुपये से नए जोखिम उभर रहे हैं। सब्जियों में तेज उतार-चढ़ाव के साथ खाद्य मुद्रास्फीति 4.20% तक चढ़ गई - टमाटर की कीमतों में 35.28% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आलू और प्याज की कीमतों में काफी गिरावट आई, जिससे आवश्यक वस्तुओं में असमान मूल्य दबाव दिखाई दिया। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती आयात लागत और ऊर्जा की कीमतें आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकती हैं
- भारत ने देश के शिपिंग और ट्रेड इकोसिस्टम को मजबूत करने और विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिए \$1.5 बिलियन का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMI पूल) लॉन्च किया है। \$1.4 बिलियन की सॉवरेन गारंटी के साथ इस पहल का मकसद भारत से आने-जाने वाले जहाजों के लिए स्थिर और लगातार इंश्योरेंस कवरेज देना है, जिसमें ग्लोबल समुद्री रास्ते और ज़्यादा जोखिम वाले इलाके शामिल हैं। यह पूल हल और मशीनरी, कार्गो इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन और इंडेन्निटी (P&I), और युद्ध जोखिम इंश्योरेंस जैसा पूरा कवरेज देता है, जिससे इंटरनेशनल शिपिंग के सभी स्टेज में सुरक्षा पक्की होती है। अप्रैल 2026 में यूनियन कैबिनेट से मंजूर, BMI पूल को इंश्योरेंस की लागत कम करने, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और ग्लोबल रुकावटों और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के दौरान भारत के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

**BONUS BONANZA SALE**

**18 Months**

Test Prime

MRP ~~₹999/-~~ **₹299**

- भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने अपना अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है, वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹ 1.98 लाख करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया , जो लाभप्रदता का लगातार चौथा वर्ष है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 3.21 लाख करोड़ हो गया , जिसे मजबूत ऋण वृद्धि, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और बैंकों में उच्च आय के स्तर का समर्थन मिला। PSB ने भी मजबूत विस्तार दिखाया, कुल कारोबार ₹ 283.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया , जमा ₹ 156.3 लाख करोड़ पर और सकल अग्रिम 15.7% साल-दर-साल बढ़ रहा है , जो ऋण की मजबूत मांग को दर्शाता है। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, सकल एनपीए 1.93% और शुद्ध एनपीए 0.39% तक गिर गया
- भारत ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है , यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारतीय रुपये पर दबाव कम करने के उद्देश्य से किया गया है। वित्त मंत्रालय के तहत संशोधित संरचना में 10% मूल सीमा शुल्क (BCD) और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) शामिल है , जिससे सोने और चांदी के लिए प्रभावी शुल्क 6% से बढ़कर 15% और प्लैटिनम के लिए 15.4% हो गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत कच्चे तेल की लागत, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण बढ़ते आयात दबावों का सामना कर रहा है , जो चालू खाता घाटे को बढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि उच्च शुल्क से सोने की मांग में 10-15% की कमी आएगी, जिससे आभूषण और निवेश की खरीदारी अधिक महंगी हो जाएगी, जबकि गैर-जरूरी विदेशी मुद्रा बहिर्वाह को रोकने में मदद मिलेगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर फाइनेंशियल हालत, खराब कमाई की संभावना और जमाकर्ताओं के हितों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। आदेश के बाद, बैंक अब 12 मई, 2026 के बाद जमा स्वीकार नहीं कर सकता, निकासी की अनुमति नहीं दे सकता, लोन जारी नहीं कर सकता या रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता, जिससे ग्राहकों के खाते प्रभावी रूप से फ्रीज हो जाएंगे। RBI ने स्पष्ट किया कि लगभग 98.36% जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के तहत सुरक्षित हैं, जो प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता ₹ 5 लाख तक के जमा को कवर करता है , जिसमें बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और अर्जित ब्याज शामिल हैं। हालांकि, ₹ 5 लाख से अधिक बैलेंस वाले जमाकर्ताओं को देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीमित सीमा से अधिक की वसूली लिक्विडेशन प्रक्रिया, बैंक संपत्तियों की बिक्री और नियुक्त लिक्विडेटर की देखरेख में दावों के निपटान पर निर्भर करेगी।
- उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर बनाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है , जो इसके एक खास ग्लोबल मार्केट में इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा विस्तार है। यह घोषणा अहमदाबाद में दारा खोसरोशाही और गौतम अडानी के बीच हुई मीटिंग के बाद की गई। यह फैसिलिटी उबर की ग्लोबल ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने, स्केल करने और डिप्लॉय करने की

क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे भारत के मजबूत इंजीनियरिंग टैलेंट , डिजिटल इकोनॉमी और बढ़ते AI और क्लाउड इकोसिस्टम का फायदा मिलेगा। डेटा सेंटर रियल-टाइम ऐप सर्विस , AI सिस्टम और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। यह कदम अडानी के AI-रेडी, ग्रीन-पावर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिशों से भी जुड़ा है।

- फिनबॉक्स ने एटलस लॉन्च किया है , जो भारत के डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में लोन प्रोसेसिंग को तेज़ करने और बॉरोअर ड्रॉप-ऑफ को कम करने के लिए एक AI-नेटिव लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म दो मॉड्यूल— एटलस फ्लो और एटलस ओरिजिन के ज़रिए ऑनबोर्डिंग और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग को ऑटोमेट करता है , जिसमें बातचीत वाले और AI-ड्रिवन वेरिफिकेशन टूल का इस्तेमाल होता है।
- यह लोन अप्रूवल का समय लगभग 21 दिन से घटाकर 24 घंटे कर देता है, जिसमें 85% एप्लीकेशन कम्प्लीशन और कम मैनुअल गलतियाँ जैसे सुधार बताए गए हैं। एजेंटिक AI से चलने वाला एटलस बैंकों और NBFC को अंडरराइटिंग और फ्रॉड का पता लगाने में मदद करता है, जिससे तेज़, ज़्यादा कुशल और स्केलेबल क्रेडिट डिलीवरी में मदद मिलती है।
- भारत का होलसेल प्राइस इंडेक्स (थोक मूल्य सूचकांक) अप्रैल 2026 में बढ़कर 8.3% हो गया , जो लगभग 3.5 साल में इसका सबसे ऊंचा लेवल है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल की दिक्कतों की वजह से फ्यूल और एनर्जी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी है। फ्यूल और पावर सेगमेंट में महंगाई बढ़कर 24.71% हो गई, जिसमें पेट्रोल (32.40%) , डीज़ल (25.19%) , और LPG (10.92%) में बड़ी बढ़ोतरी हुई , जो दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाय की अनिश्चितता को दिखाता है। मुख्य लेख महंगाई यह भी बढ़कर 9.17% हो गया , जबकि मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़कर 4.62% हो गई , जो पूरी इकॉनमी में कीमतों पर बड़े पैमाने पर दबाव दिखाता है। चूंकि WPI प्रोड्यूसर-लेवल की लागत को ट्रैक करता है, इसलिए लगातार ऊंची महंगाई का असर आखिरकार कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है, जिससे रिटेल कीमतें बढ़ेंगी और भारत के ओवरऑल महंगाई के आउटलुक पर दबाव बढ़ेगा।
- HDB फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने नटराजन श्रीनिवासन को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है। यह अपॉइंटमेंट ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी अपने ऑपरेशन्स को बढ़ा रही है और अपनी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही है। श्रीनिवासन मुरुगप्पा ग्रुप से लीडरशिप का बहुत अनुभव लेकर आए हैं, जहाँ उन्होंने कई सीनियर मैनेजमेंट रोल्स निभाए हैं। इस बीच, कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने अनाउंस किया है कि उसकी लेंडिंग ब्रांच, कैप्री लोन्स , ने पूरे भारत में 1,000 गोल्ड लोन ब्रांच पार कर ली हैं। यह एक्सपेंशन शहरी, सेमी-अर्बन और ग्रामीण मार्केट में तेज़ और ट्रांसपेरेंट गोल्ड-बैंकड क्रेडिट तक पहुँच को मजबूत करता है। 2022 में अपना गोल्ड-लोन बिज़नेस लॉन्च करने के बाद से, कैप्री लोन्स तेज़ी से बढ़ा है, जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹ 16,960 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं , जो कंपनी के बड़े फाइनेंशियल इनक्लूजन गोल्स को सपोर्ट करता है।

- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एन्युइटी से बाहर निकलने के नियमों में ढील दी है, जिससे खास मुश्किल हालात में एन्युइटी प्लान को सीमित तौर पर सरेंडर करने की इजाजत मिल गई है। इस बदले हुए फ्रेमवर्क से मुख्य रूप से उन रिटायर लोगों को फायदा होगा जिन्हें गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है या जिनके पास पुरानी एन्युइटी पॉलिसी हैं जिनमें पहले से ही सरेंडर के नियम शामिल हैं। पहले, जब रिटायर

लोग अपने NPS कॉर्पस का इस्तेमाल एन्युइटी खरीदने के लिए करते थे, तो छोटे "फ्री लुक" कैसलेशन पीरियड को छोड़कर प्लान से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। नए नियमों के तहत, एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) अब सरेंडर की इजाजत दे सकते हैं अगर एन्युइटी लेने वाला या परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मौजूदा सरेंडर क्लॉज वाले 24 अक्टूबर, 2024 से पहले के कुछ एन्युइटी प्लान भी इसके लिए योग्य हो सकते हैं।

## नियुक्तियाँ/इस्तीफे

- चेररमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाला है। यह भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनियों में से एक में एक अहम लीडरशिप बदलाव है। SAIL में तीन दशकों से ज़्यादा के अनुभव के साथ, उन्होंने 1992 में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर शुरुआत की और बाद में डायरेक्टर (फाइनेंस) और डायरेक्टर (कमर्शियल) जैसे सीनियर पदों पर काम किया, जिससे मज़बूत इंटरनल लीडरशिप ग्रोथ दिखाई दी। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पूरे ऑर्गनाइज़ेशन में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्ट मिक्स, सेल्स वॉल्यूम, नेट सेल्स रियलाइज़ेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्ट्रेटैजिक मार्केट अलाइनमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। SAIL के लिए उनके विज्ञान में कैपेसिटी को 35 MTPA तक बढ़ाना, सेफ्टी, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, ब्रांडिंग और मार्केट ग्रोथ को मज़बूत करना, स्टील प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के बड़े लक्ष्य को सपोर्ट करना शामिल है।
- विदेश मंत्रालय ने प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है।
- 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर, वे अभी एडिशनल सेक्रेटरी (इमिग्रेशन पॉलिसी और वेलफेयर) के तौर पर काम कर रहे हैं और मस्कट में गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास की जगह लेंगे। प्रशांत पिसे के पास काफ़ी डिप्लोमैटिक अनुभव है, जिसमें काहिरा, त्रिपोली में पोस्टिंग, रूस, सेंट्रल एशिया, CIS मामले, और UN के आर्थिक मामलों से जुड़े रोल, साथ ही इंटरनेशनल माइग्रेशन और लेबर डिप्लोमेसी में लीडरशिप शामिल है। उनकी नियुक्ति स्ट्रेटैजिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान एनर्जी सिक्योरिटी, समुद्री सहयोग,

व्यापार और बड़े भारतीय डायस्पोरा के कल्याण के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक प्रमुख भारतीय पार्टनर बना हुआ है।

- राजीव मेमानी की जगह लेते हुए 2026-27 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट का पद संभाला है। तीन दशकों से ज़्यादा के लीडरशिप अनुभव वाले टाटा ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव, मुकुंदन ने केमिकल्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जैसे कई सेक्टर में काम किया है, और अभी टाटा केमिकल्स को लीड कर रहे हैं। CII ने सुचित्रा के एला को 2026-27 के लिए प्रेसिडेंट-डेसिग्रेट और शाश्वत गौयनका को वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर भी अनाउंस किया है। भारत की सबसे असरदार इंडस्ट्री बॉडीज़ में से एक के तौर पर, CII इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिसी एडवोकेसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, मैनुफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस और पब्लिक-प्राइवेट डायलॉग में अहम रोल निभाता है।
- सेंट स्टीफंस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल बनाया गया है, जो इंस्टीट्यूशन के 145 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वह 1 जून 2026 से 14वीं प्रिंसिपल के तौर पर पद संभालेंगी, और जॉन वर्गीस की जगह लेंगी। तीन दशकों से ज़्यादा के अनुभव वाली एक अनुभवी एकेडमिक, एलियास ने टीचिंग, रिसर्च और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, और इससे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में प्रो वाइस चांसलर (रिसर्च) के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनके विज्ञान में कॉलेज की विरासत को बनाए रखना और मॉडर्न, भविष्य के लिए तैयार कोर्स शुरू करना शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में, संस्थान को उभरते वैश्विक शिक्षा रुझानों के साथ संरेखित करना।

## रक्षा समाचार

- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने हैदराबाद में एक स्कैमजेट कम्बस्टर का सफल टेस्ट किया, जिसने 1,200 सेकंड से ज़्यादा का रनटाइम हासिल किया, जिससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रोग्राम और एयरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा मिला। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा विकसित, यह सिस्टम स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें भारत में बना फ्यूल, एडवांस्ड कोटिंग्स और हाई-टेम्परेचर ऑपरेशन के लिए मॉडर्न मैनुफैक्चरिंग तरीके शामिल हैं। स्कैमजेट इंजन मिसाइलों को Mach 5 से ऊपर की स्पीड से चलने में सक्षम बनाता है, पारंपरिक रॉकेट सिस्टम की तुलना में हल्के और ज़्यादा कुशल
- हाइपरसोनिक प्रोपल्शन के लिए एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। यह उपलब्ध अगली पीढ़ी की डिफेंस टेक्नोलॉजी

में भारत की स्थिति को मज़बूत करती है, जिससे मिसाइल डिफेंस से बचने, हाई-स्पीड युद्ध और स्ट्रेटैजिक सुरक्षा में क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए विदेशी निर्भरता कम होती है।

- भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बनाया गया मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एयरबस C-295, बडोदरा में टाटा-एयरबस फैसिलिटी से फाइनल रोलआउट के करीब है। एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच पार्टनरशिप से बना यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। रक्षा लक्ष्य। 2021 के रक्षा सौदे के तहत, भारत को 56 C-295 विमान मिलेंगे, जिनमें से 16 स्पेन से आयात किए जाएंगे और 40 भारत में बनाए जाएंगे। गुजरात में अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन 2024 में नरेंद्र मोदी और पेद्रो सांचेज़ ने किया था।

- C-295 एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल टूप ट्रांसपोर्ट, कार्गो मूवमेंट, मेडिकल इवैक्युएशन और स्पेशल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यह छोटी और ऊबड़-खाबड़ एयरस्ट्रिप से ऑपरेट कर सकता है और 9,000 kg से ज्यादा पेलोड या लगभग 71 लोगों को ले जा सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने, प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैनुफैक्चरिंग को बढ़ाने, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने और एडवांस्ड घरेलू सप्लाइ चैन बनाने की उम्मीद है।
- डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा विकसित AI-संचालित लड़ाकू विमान 'काल भैरव' के साथ एक प्रमुख रक्षा नवाचार मील का पत्थर हासिल किया, जिसे पुर्तगाल में निर्मित किया जाना है। यह एक स्वायत्त लड़ाकू विमान का भारत का पहला विदेशी उत्पादन है और व्यापक ऑपरेशन 777 पहल का हिस्सा है। MALE (मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंजोरेंस) विमान में 3,000 किमी की रेंज, 30+ घंटे की धीरज, AI-आधारित लक्ष्य पहचान, झुंड समन्वय और सुरक्षित एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली है। यह आधुनिक युद्ध में निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने

और सटीक लड़ाकू मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। पुर्तगाल में उत्पादन SKETCHPIXEL LDA के साथ साझेदारी के माध्यम से होगा

- राजनाथ सिंह और एन. चंद्रबाबू नायडू ने श्री सत्य साई जिले में ₹ 15,803 करोड़ की उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। AMCA कार्यक्रम का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। विमान में उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकी, अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स, उच्च उत्तरजीविता और आधुनिक लड़ाकू क्षमताएं होंगी, जो भारत को उन्नत लड़ाकू विमान विकास विशेषज्ञता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करेगी। पुट्रपथी में लगभग 650 एकड़ में फैली इस सुविधा में असेंबली, सिस्टम परीक्षण, उड़ान सत्यापन और प्रोटोटाइप मूल्यांकन के लिए एक विमान एकीकरण और उन्नत उड़ान परीक्षण केंद्र शामिल होगा

### पुरस्कार और सम्मान

- द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल नर्स डे पर राष्ट्रपति भवन में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल् अवॉर्ड्स 2026 दिए। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किए गए ये अवॉर्ड्स, बेहतरीन नर्सिंग प्रोफेशनल्स को उनके डेडिकेशन, कम्पैशन और हेल्थकेयर सर्विस के लिए सम्मानित करते हैं। अवॉर्ड पाने वालों में भारत के अलग-अलग राज्यों और इंस्टीट्यूशन्स

से कुलविंदर पारही, उज्वला महादेव सोयम, लालेंथांगी हनमटे, गीता करमाकर और मेजर जनरल लिस्ममा पीवी शामिल थे। 2026 की थीम, "हमारी नर्सों। हमारा भविष्य। एम्पावर्ड नर्सों जान बचाती हैं," देश भर में नर्सों के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशंस, लीडरशिप के मौके और क्वालिटी ट्रेनिंग पर जोर देती है।

### खेल समाचार

- 10 मई 2026 को चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 13 गेंदों में फिफ्टी लगाकर, वह IPL की सबसे तेज हाफ सेंचुरी की लिस्ट में शामिल हो गए। अब वह यशस्वी जायसवाल के साथ टॉप पर हैं, जिन्होंने सबसे पहले IPL 2023 में राजस्थान रॉयल्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। IPL की सबसे तेज फिफ्टी का चार्ट तेजी से बदला है, जिसमें केएल राहुल, यूसुफ पठान, निकोलस पूरन और दूसरे खिलाड़ियों ने पिछले कुछ सालों में धमाकेदार पारियां खेली हैं। IPL 2026 में, वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट ने भी सुर्खियां बटोरीं, जिससे मॉडर्न T20 क्रिकेट में लीग के अल्ट्रा-फास्ट स्कोरिंग और पावर हिटिंग के बढ़ते ट्रेंड का पता चला।
- सार्डिनिया विश्व शतरंज महोत्सव 2026 में, फौस्टिनो ओरो सिर्फ 12 साल, 6 महीने, 26 दिन की उम्र में इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बन गए, उन्होंने अपना अंतिम जीएम मानदंड पूरा किया और कुलीन शतरंज में अपनी बढ़त को मजबूत किया।
- "शतरंज के मेस्सी" का उपनाम, वह केवल अभिमन्यु मिश्रा का अनुसरण करते हैं, जिनके पास सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है, और डी गुकेश और आर प्रग्यानंधा जैसे खिलाड़ियों सहित विलक्षण खिलाड़ियों के एक विशेष समूह में शामिल हो गए हैं।
- ब्यूनस आयर्स में जन्मे ओरो ने शीर्ष स्तर के विरोधियों को हराने और बहुत कम उम्र में असाधारण
- स्थिति कौशल, परिपक्वता और निडर आक्रमण शैली दिखाने के बाद वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। उनकी उपलब्धि दुनिया भर में किशोर शतरंज प्रतिभाओं के बढ़ते प्रभुत्व को उजागर करती है

- शंघाई में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में, दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोद की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने एक रोमांचक शूट-ऑफ फाइनल में मेज़बान देश चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता। मैच में कांटे की टक्कर हुई, चार सेट के बाद मुकाबला बराबरी पर रहा, फिर भारत ने चीन को 28-26 से हराया, जिसमें दीपिका कुमारी ने नौ पॉइंट के अहम तीर से जीत पक्की की। इस जीत में ओलंपिक आर्चरी में एक बड़ी ताकत, दक्षिण कोरिया पर एक बड़ा सेमीफाइनल उलटफेर भी शामिल था, जिसने रिकर्व आर्चरी में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया। यह 2021 के बाद भारत का पहला आर्चरी वर्ल्ड कप गोल्ड है, जिससे महिला टीम के कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
- डबलिन गार्डियंस फ्रैंचाइज़ के मालिक बन गए हैं। यह यूरोप का पहला ICC-सेक्शनल मल्टी-कंट्री T20 कॉम्पिटिशन है। ETPL को क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया जा रहा है ताकि पूरे यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा सके। द्रविड का शामिल होना अहम माना जाता है क्योंकि वे भारत के पूर्व कप्तान, वर्ल्ड कप जीतने वाले कोच और यूथ क्रिकेट डेवलपमेंट में मेंटर के तौर पर जाने जाते हैं, जिससे लीग को दुनिया भर में मजबूत क्रेडिबिलिटी मिली है। इस लीग में क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव वॉ और फाफ डू प्लेसिस जैसी स्टार-स्टडेड फ्रैंचाइज़ ओनरशिप भी है, और ETPL 2026 में बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

- 9 गोल्ड मेडल सहित कुल 27 मेडल जीते। यह उपलब्धि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की युवा बॉक्सिंग प्रतिभा के उदय को दिखाती है। U-15 लड़कियों की टीम सबसे बड़ी योगदानकर्ता के रूप में उभरी, जिसने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते। गोल्ड मेडल जीतने वालों में अंजी (37kg), सोनिया (40kg), तन्वी (43kg), हंसिका अत्री

(46kg), सुनैना (58kg), भूमिका (61kg) और एंजेल (70kg) शामिल हैं। U-15 लड़कों की टीम ने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते, जिसमें यश कुमार (33kg) और मोहम्मद यासर (58kg) ने गोल्ड मेडल हासिल किए। भारत ने चैंपियनशिप में कुल 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते।

### योजनाएँ और समितियाँ समाचार

- भारत घरेलू मैनुफैक्चरिंग को मज़बूत करने और खास इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम शुरू करने का प्लान बना रहा है। सरकार लोकल प्रोडक्शन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोबाइल एक्सल और मोटरसाइकिल कंपोनेंट समेत करीब 100 प्रोडक्ट्स की पहचान कर सकती है। इस स्कीम में शायद मेड इन इंडिया सर्टिफिकेशन, क्वालिटी बेंचमार्क और भारत में बने प्रोडक्ट्स पर भरोसा बढ़ाने के लिए एक खास लोगो लाया जाएगा। यह पहल मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम जैसे बड़े प्रोग्राम और ग्लोबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs) के ज़रिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की भारत की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करती है।
- सुवेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम की घोषणा की, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में योग्य महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए हर महीने ₹ 3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह स्कीम 1 जून, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जिसका मकसद महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को मज़बूत करना और पहले की लक्ष्मी योजना की जगह लेना है। भंडार ज़्यादा यूनिकॉर्म फ़ायदों वाली स्कीम। नई सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सफ़र को भी मंजूरी दी और आयुष्मान भारत, PM विश्वकर्मा, और प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना जैसी सेंट्रल स्कीमों को लागू करने का ऐलान किया। कैबिनेट के दूसरे फ़ैसलों में बॉर्डर पर फ़ेंसिंग के लिए BSF को ज़मीन देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे वेलफ़ेयर प्रोग्राम, और राज्य में सोशल सिक्योरिटी के उपायों को बढ़ाना शामिल था।

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ने पुणे में WISE 2026 इनोवेशन मीट के दौरान एक खास मौसम और क्लाइमेट स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया। NEAT और मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंसेज़ के मिशन मौसम के तहत डेवलप किए गए इस सेंटर का मकसद क्लाइमेट एनालिटिक्स, फोरकास्टिंग, रेजिलिएंस टूल्स और वेदर टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। इस इवेंट ने साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को क्लाइमेट इंटेलेजेंस को प्रैक्टिकल बिज़नेस सॉल्यूशंस में बदलने के लिए जोड़ा। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑर्गनाइज़ेशन्स के सपोर्ट से, यह इनिशिएटिव इनोवेशन, कोलेबोरेशन और एडवांस्ड क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए मौसम के लिए तैयार और क्लाइमेट-स्मार्ट देश बनने के भारत के विज़न को मज़बूत करता है।
- एंडेजर्ड स्पीशीज़ डे पर काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व में अपना पहला सैटेलाइट-टैग वाला गंगा साँपशेल कछुआ छोड़ा, जो वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ब्रह्मपुत्र बेसिन में कंज़र्वेशन प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए कछुओं की मूवमेंट, ब्रीडिंग साइट्स और हैबिटाट के इस्तेमाल को ट्रैक करना है। वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया, असम फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नेशनल ज्योग्राफ़िक सोसाइटी के सपोर्ट से, यह पहल असम की बायोडायवर्सिटी की कोशिशों को हाईलाइट करती है। एंडेजर्ड कछुआ एक नेचुरल स्कैवेन्जर के तौर पर एक अहम इकोलॉजिकल रोल निभाता है, जो ताज़े पानी के इकोसिस्टम की हेल्थ और नदी की सफ़ाई बनाए रखने में मदद करता है।

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की कुलजीत कौर मरहास, उल्कापिंडों, आइसोटोप और ग्रह विज्ञान में अपने शानदार काम के लिए मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
- उनकी रिसर्च प्री-सोलर ग्रेन, CAIs, कॉन्डूल और शॉर्ट-लिव्ड रेडियोन्यूक्लाइड पर स्टडी के ज़रिए सोलर सिस्टम की शुरुआत का पता लगाती है, जिससे साइंटिस्ट को चार अरब साल पहले ग्रहों के बनने को समझने में मदद मिलती है।
- SIMS और nanoSIMS जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उन्होंने स्टारडस्ट, हायाबुसा और अपोलो प्रोग्राम जैसे बड़े मिशन के सैंपल का एनालिसिस किया है। यह पहचान
- स्पेस रिसर्च, कॉस्मोकेमिस्ट्री और ग्रहों के मटीरियल एनालिसिस में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है, साथ ही एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।



**महत्वपूर्ण दिन**

- भारत 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की याद में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाता है , लेकिन 2026 में टेक्नोलॉजी नौकरियों, शिक्षा, AI, हेल्थकेयर, स्टार्टअप्स, साइबर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर बन गई है । आज, UPI पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विसेज़, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल रही हैं और पूरे भारत में इंडस्ट्रीज़ को नया आकार दे रही हैं। भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने और विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम करने के लिए सेमीकंडक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस इनोवेशन में तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है। यह दिन डिजिटल लिटरेसी, फ्यूचर-रेडी स्किल्स और टेक्नोलॉजी तक सभी की पहुंच की ज़रूरत पर भी ज़ोर देता है , क्योंकि इनोवेशन तेज़ी से एम्प्लॉयबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी और लॉन्ग-टर्म इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस तय कर रहा है।
- 12 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्स डे 2026 मनाया गया। यह ग्लोबल हेल्थकेयर सिस्टम में नर्सों के समर्पण, त्याग और सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम, “हमारी नर्सों! हमारा भविष्य। मज़बूत नर्सों जानें बचाती हैं,” बेहतर ट्रेनिंग, सुरक्षा, लीडरशिप और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत पर ज़ोर देती है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, जिन्हें क्रीमियन युद्ध के दौरान उनके काम के लिए “द लेडी विद द लैंप” के नाम से जाना जाता है। 130 से ज़्यादा देशों में मनाया जाने वाला यह मौका महामारी, आपदाओं और हेल्थकेयर इमरजेंसी के दौरान नर्सों की फ्रंटलाइन भूमिका को पहचान देता है और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है।
- मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक 2026, 11-17 मई तक “एक्शन” थीम के साथ मनाया जा रहा है , जो मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल कदमों को बढ़ावा देता है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा ऑर्गनाइज़ और NHS और माइंड द्वारा सपोर्टेड, यह कैम्पेन उम्मीद, रोकथाम और इंसानी कनेक्शन पर फोकस करता है। यह पहल फिजिकल एक्सरसाइज़ , माइंडफुलनेस , इमोशनल सपोर्ट, बॉलेंटियरिंग और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वेयर इट ग्रीन डे में हिस्सा लेने जैसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है । एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ग्लोबल मेंटल हेल्थ नतीजों को बेहतर बनाने के लिए शुरुआती सपोर्ट, वर्कप्लेस स्ट्रेस कम करना, इमोशनल एजुकेशन और मज़बूत कम्युनिटी कनेक्शन ज़रूरी हैं ।
- इंटरनेशनल डे ऑफ़ प्लांट हेल्थ हर साल 12 मई को मनाया जाता है । इसका मकसद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन की गाइडेंस में, पौधों को कीड़ों, बीमारियों और पर्यावरण के खतरों से बचाने के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। 2026 की थीम, “फूड सिक्योरिटी के लिए प्लांट बायोसिक्योरिटी,” ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल खेती और बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा पक्का करने के लिए फसलों और इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने की ज़रूरत पर ज़ोर देती है

- । पौधे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वे दुनिया का ज़्यादातर खाना और ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा देते हैं, जिससे पौधों की हेल्थ इंसान के ज़िंदा रहने, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरण संतुलन के लिए ज़रूरी हो जाती है । यह दिन FAO और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन (IPPC) के अहम ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के साथ, इंसान, जानवर, पौधे और पर्यावरण की हेल्थ को जोड़ने वाले वन हेल्थ अप्रोच को भी सपोर्ट करता है।
- इंटरनेशनल डे ऑफ़ फ़ैमिलीज़ 2026, 15 मई को समाज में परिवारों की भूमिका को हाईलाइट करने और दुनिया भर में फ़ैमिली वेलबीइंग को मज़बूत करने वाली पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है । थीम “फ़ैमिलीज़, इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबीइंग” इस बात पर फोकस करती है कि बढ़ती इनकम इनइक्वालिटी , हेल्थकेयर और एजुकेशन तक सीमित एक्सेस , और सोशल प्रोटेक्शन की कमी बच्चों के डेवलपमेंट पर कैसे असर डालती है। यह चाइल्डकेयर, पैरेंटल लीव, और गरीबी कम करने के उपायों जैसे मज़बूत सपोर्ट सिस्टम की मांग करता है । यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया यह दिन , ज़्यादा इनक्लूसिव सोसाइटी बनाने पर ग्लोबल चर्चा को बढ़ावा देता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) से जुड़ा है, खासकर हेल्थ, एजुकेशन, और कम इनइक्वालिटी के एरिया में ।
  - 16 मई 2026 को अपना 51वां स्टेटहुड डे मनाया, जो 1975 में भारत में इसके ऐतिहासिक इंडीग्रेशन की याद में मनाया गया। पहले नामग्याल वंश का हिमालयी राज्य, सिक्किम एक पब्लिक रेफरेंडम और 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1975 के बाद भारत का 22वां राज्य बना । यह मौका डेमोक्रेसी, शांतिपूर्ण पॉलिटिकल बदलाव और कल्चरल बचाव का प्रतीक है । अपनी समृद्ध परंपराओं, बौद्ध विरासत और इकोलॉजिकल लीडरशिप के लिए जाना जाने वाला सिक्किम, भारत का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य है और दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा का घर है। सेलिब्रेशन में पूरे राज्य में कल्चरल इवेंट, एजुकेशनल एक्टिविटी और ऑफिशियल सेरेमनी शामिल थे।



**निधन**

- स्वपन साधन बोस, जिन्हें "टूटू बोस" के नाम से जाना जाता था, का 79 साल की उम्र में कोलकाता में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। एक बहुत सम्मानित फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर, टूटू बोस तीन दशकों से ज्यादा समय तक मोहन बागान सुपर जायंट से जुड़े रहे और उन्होंने क्लब में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जैसे बड़े रोल निभाए। उन्होंने क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाने में अहम भूमिका निभाई और

कोलकाता के फुटबॉल क्लब और इंडियन फुटबॉल मैनेजमेंट में एक असरदार हस्ती बन गए। उनके पार्थिव शरीर को मोहन बागान क्लब के टेंट में रखा जाएगा ताकि फैंस अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें, जबकि परिवार के सदस्यों और स्पोर्ट्स हस्तियों ने उन्हें इंडियन फुटबॉल में सपोर्ट और लीडरशिप के पिलर के तौर पर याद किया।

**Static Takeaways**

पहलू	विवरण
राजस्थान	मुख्यमंत्री: भजनलाल शर्मा राज्यपाल: हरिभाऊ किसानराव बागडे राजधानी: जयपुर
पश्चिम बंगाल	मुख्यमंत्री: सुबेंदु अधिकारी राज्यपाल: आरएन रवि राजधानी: कोलकाता
तमिलनाडु	मुख्यमंत्री: विजय जोसेफ राज्यपाल: राजेंद्रन आर्लेकर राजधानी: चेन्नई
असम	मुख्यमंत्री: हिमंत सरमा राज्यपाल: लक्ष्मण प्रसाद राजधानी: दिसपुर
लद्दाख	उपराज्यपाल: विनय कुमार सक्सेना
केरलम	मुख्यमंत्री: वीडी सतीशन राज्यपाल: राजेंद्रन आर्लेकर राजधानी: तिरुवनंतपुरम
यूएसए	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी: वाशिंगटन डी.सी.
चीन	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग राजधानी: बीजिंग
रूस	राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन राजधानी: माँस्को
नीदरलैंड	प्रेसिडेंट: रॉब जेटन कैपिटल: एम्स्टर्डम
संयुक्त अरब अमीरात	राष्ट्रपति: मोहम्मद अल बिन नाहयान राजधानी: अबू धाबी
मुख्य चुनाव आयुक्त	ज्ञानेश कुमार
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री	भूपेंद्र यादव
केंद्रीय कृषि मंत्री	शिवराज सिंह चौहान
यूरोपीय संघ	उर्सुला वॉन डेर लेयेन - राष्ट्रपति
सेबी	तुहिन कांता पांडे - चेयरमैन
भारतीय रिजर्व बैंक	संजय मल्होत्रा - राज्यपाल
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CJI - जस्टिस सूर्यकांत